राजस्थान समसामयिकी मार्च, 2026

संजीव Telegram, App एवं वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट का सार संग्रह;
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय समसामयिकी (प्रत्येक माह)
साथ ही संजीव App एवं वेबसाइट से आप
Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान समसामयिकी मार्च, 2026
(Current News from Daily Newspapers)

Newspaper of 1 March, 2026

■ पीएम नरेन्द्र मोदी का राजस्थान दौरा; एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, अन्य योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया–

28 फरवरी, 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत की। उन्होंने 9 से 14 साल की पांच बालिकाओं को टीका लगाए जाने के बाद उनसे संवाद भी किया। पीएम ने प्रदेश के करीब 16 हजार 686 करोड़ रुपए की सौगात दी और 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की औपचारिक शुरुआत की।

वैक्सीन की पहली डोज अजमेर जिले के गांव चाचियावास निवासी एवं नवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी मनीषा रावत को लगाई गई।

उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 2026 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के अवसर पर पूरे राजस्थान प्रदेश में उत्साह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित हुए तथा जिला मुख्यालयों पर इस अवसर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान अजमेर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

Newspaper of 2 March, 2026

■ गिव अप अभियान : 55 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सब्सिडी छोड़ी–

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गैस सब्सिडी के लिए वर्ष 2015 में चलाए गए गिव इट अप अभियान से प्रेरणा लेकर प्रदेश में संपन्न लोगों द्वारा खाद्य सब्सिडी के स्वैच्छिक त्याग के लिए गिव अप अभियान नवंबर 2024 में शुरू किया गया।

- ♦ इस अभियान के माध्यम से 55 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपने खाद्य सब्सिडी का त्याग किया, जिससे खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लोगों के लिए जगह बनी। इनमें से 6 लाख लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन अपनी खाद्य सुरक्षा छोड़ी है।
- ♦ भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, बीकानेर, खैरथल-तिजारा एवं जयपुर में सबसे अधिक सम्पन्न लोगों ने अपनी खाद्य सब्सिडी का स्वेच्छा से त्याग किया।
- ♦ राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषद की हाल ही में सम्पन्न बैठक में गिव अप अभियान की सराहना केन्द्र सरकार द्वारा की गई। वन नेशन वन राशन कार्ड से अब पात्र लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में नि:शुल्क राशन प्राप्त कर सकता है।

■ एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद–

रबी विपणन सीजन 2024-25 में 'राजस्थान कृषक समर्थन योजना' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल पर 125 रुपये प्रति क्विंटल दर से 150.66 करोड़ रुपये बोनस राशि का भुगतान कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। रबी विपणन सीजन 2025-26 में 'राजस्थान कृषक समर्थन योजना' के तहत गेहूं एमएसपी के ऊपर 150 रुपये का बोनस देकर कुल 2,575 रुपये प्रति क्विंटल पर 21.37 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद कर 1,72,679 किसानों को लाभान्वित कर 320.50 करोड़ रुपये बोनस दिया गया। आने वाले रबी विपणन सीजन में विभाग द्वारा लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद सुनिश्चित कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

■ तीन जिलों में अनाज एटीएम स्थापित होंगे–

विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में तीन अनाज एटीएम स्थापित करने के लिए जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों का चयन किया गया है।

- ♦ अनाज एटीएम की स्थापना से राशन वितरण की प्रक्रिया सुगम तथा पारदर्शी होगी एवं लाभार्थियों को 24 घंटे अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी।
- ♦ नवाचार के क्रम में विभाग द्वारा अप्रैल 2026 से उचित मूल्य दुकानों में गेहूं का आवंटन 50 किलो के न्यूनतम माप से ही किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- ♦ इससे अधिक गेहूं जाने पर अगले माह में उतना गेहूं आवंटन से काट लिया जाएगा तथा कम जाने पर आवंटन में अधिक अनाज जोड़ दिया जाएगा।
- ♦ एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं को अप्रैल 2026 से विभाग द्वारा रियायती गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- अब तक बाजार मूल्य पर गेहूं एवं चावल की खरीद कर इन छात्रावासों में आपूर्ति की जा रही थी। अब 4.15 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं एवं 5.65 रुपये प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति इन छात्रावासों को विभाग द्वारा की जाएगी।
- इसके लिए 20 करोड रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
- प्रथम चरण में इस योजना से 35,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

Newspaper of 6 March, 2026

राजस्थान विधानसभा में 'राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2026' ध्वनिमत से पारित हुआ–

5 मार्च, 2026 को विधानसभा ने राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद राज्य में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कर्मचारियों से दैनिक अधिकतम 10 घंटे तक काम लिया जा सकेगा, हालांकि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही रहेगी। साथ ही प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु बढ़ाने और ओवरटाइम की सीमा बढ़ाने जैसे कई नए प्रावधान भी लागू होंगे।

संशोधन का उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाना है। महिलाओं के रात्रिकालीन कार्य से जुड़े नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। लगातार काम करने की अधिकतम अवधि भी 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है, जिसके बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। बच्चों के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। इससे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकान या वाणिज्यिक संस्थानों में काम पर नहीं रखा जा सकेगा।

मुख्य प्रावधान

- दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में दैनिक कार्य समय 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया
- साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे
- ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 144 घंटे
- लगातार काम के बाद विश्राम की सीमा 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे

बच्चों से जुड़े नियम

- प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक
- किशोरों की आयु श्रेणी अब 14 से 18 वर्ष
- 14 से 18 वर्ष के किशोरों से रात्रि में काम नहीं लिया जा सकेगा।

Newspaper of 7 March, 2026

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित

समाज में अनुशासन और विश्वास पैदा होगा–

5 मार्च, 2026 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया।

- यह विधेयक न तो किसी न्यायिक क्षेत्राधिकार को और न ही कार्यपालिका के अधिकारों को कम करने और बढ़ाने के लिए है, न ही न्यायपालिका के अधिकारों को छीनता है। यह प्रशासनिक सुधार के साथ नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है।
- इस विधेयक से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग के मूलमंत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- पूर्व के अधिनियम छोटे उल्लंघन या तकनीकी चूक के लिए भी कारावास जैसी आपराधिक शास्तियां अधिरोपित करते हैं।
- इससे अत्यधिक मुकदमेबाजी होने पर न्यायिक प्रणाली पर भार पड़ता गया है।
- इससे आमजन, व्यावसायियों सहित अन्य को अनावश्यक कठिनाइयां हो रही हैं। इसलिए राज्य सरकार अब कारावास के स्थान पर शास्तियों के उपबंधों को प्रतिस्थापित करती है।
- इससे अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से आमजन को राहत मिलेगी।
- इससे निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी।
- इससे कानून कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनेगा।
- राज्य सरकार अपराधियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रही है।
- यह गंभीर अपराधों को समाप्त नहीं करता बल्कि बार-बार अपराध करने वालों पर कठोर दंड का भी प्रावधान करता है।
- इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955, राजस्थान नौचालन विनियम अधिनियम 1956, राजस्थान भाण्डागार अधिनियम 1958, राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग)

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

अधिनियम 1961, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1962, राजस्थान साहूकार अधिनियम 1963, राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम 2018 के उपबंधों में संशोधन किया गया है।

बिना लाइसेंस भंडारण पर 50 हजार रुपये तक की शास्ति

राजस्थान भाण्डागार अधिनियम 1958 के तहत बिना लाइसेंस भंडारण किए जाने पर पहले एक साल तक का कारावास और 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान था।

- ♦ इसमें संशोधन करते हुए अब कारावास को हटाकर शास्ति राशि को ही 50 हजार रुपये तक बढ़ाया गया है।
- ♦ साथ ही, घरेलू पेयजल कनेक्शन के गैर घरेलू उपयोग पर पहले एक वर्ष तक कारावास का प्रावधान था।
- ♦ इसमें अब कारावास प्रावधान को हटाकर प्रतिदिन न्यूनतम 200 रुपये से अधिकतम 1 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना का प्रावधान रखा गया है।
- ♦ राज्य सरकार विधानसभा में खेजड़ी संरक्षण को लेकर कानून लगाएगी।

Newspaper of 8 March, 2026

■ राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ–

7 मार्च, 2026 को कोटा-बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। 440 हेक्टेयर में 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एयरपोर्ट दिसंबर 2027-28 तक पूरा हो जाएगा।

एयरपोर्ट से कारोबार, रोजगार और पर्यटन का विकास तेजी से होगा। यहां कृषि और बेहतर सड़क-रेल कनेक्टिविटी से हाड़ौती क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

कोटा-बूंदी एयरपोर्ट एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि हाड़ौती की आर्थिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। उद्योग, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी की कमी थी। अब कोटा देश ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़ सकेगा। कोटा आईटी का नया हब भी बनेगा।

कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एक नजर में

- ♦ लागत 1507 करोड़
- ♦ भूमि 440 हेक्टेयर
- ♦ क्षमता 20 लाख यात्री/वर्ष
- ♦ टर्मिनल 20,000 वर्गमीटर
- ♦ रनवे : 3200 मी. लंबा, 45 मी. चौड़ा
- ♦ A-321 जैसे बड़े विमान उतरेंगे
- ♦ 2027-28 तक इसका संचालन
- ♦ हाड़ौती के यात्री जयपुर आते हैं। ऐसे में जयपुर में दबाव कम होगा।

राजस्थान को फायदा

- ♦ पर्यटन बढ़ेगा (बूंदी, चंबल, रणथंभौर) और उद्योग व व्यापार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

Newspaper of 10 March, 2026

■ राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित–

9 मार्च, 2026 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित किया गया

- ♦ अजमेर में विश्वविद्यालय की स्थापना ऐतिहासिक पहल है।
- ♦ इससे 'स्वस्थ राजस्थान से समृद्ध राजस्थान' के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।
- ♦ विश्वविद्यालय के लिए बजट वर्ष 2024-25 में घोषणा की गई थी।
- ♦ इसकी स्थापना से अब उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाओं में अधिक गुणवत्ता सुदृढ़ होगी।
- ♦ यह विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान का केन्द्र बनेगा।
- ♦ विश्वविद्यालय के जरिए आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा।
- ♦ इसमें चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों के आविष्कारों को शामिल किया जाएगा।
- ♦ इसके क्षेत्राधिकार को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी।
- ♦ अधिनियम के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रबंध, विद्या, संकाय, अध्ययन, वित्त और लेखा समिति, अनुसंधान, खेल एवं छात्र कल्याण और नवाचार बोर्ड होंगे। कुलाधिपति द्वारा कुलगुरु की नियुक्ति किए जाने के बाद प्रबंध बोर्ड का गठन होगा।
- ♦ विश्वविद्यालय में संकाय बोर्ड के अन्तर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अन्य संकायों में अध्ययन होगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- इस विश्वविद्यालय के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की भूमि में से 11.93 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है।

Newspaper of 11 March, 2026

राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) बिल 2026 पारित हुआ–

10 मार्च, 2026 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) बिल 2026 पारित हुआ। राजस्थान सरकार ने निकाय चुनावों में 30 साल पुराने उस नियम को हटा दिया है, जो दो से ज्यादा बच्चों वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोड़ा बना हुआ था। इसके साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी दशकों पुरानी पाबंदी भी हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव खत्म करने के आदेश दिए थे। नगरपालिका एक्ट की धारा 18(2) में संशोधन के बाद अब तीसरी संतान अयोग्यता का कारण नहीं बनेगी। इस मामले में सरकार का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर केवल जनप्रतिनिधियों पर यह पाबंदी थोपना तर्कसंगत नहीं था। उल्लेखनीय है कि अनेकों जनप्रतिनिधि 1995 के बाद तीसरी संतान होने के कारण चुनावी दौड़ से बाहर होते आ रहे थे। आगामी 196 निकायों के चुनाव में अब उम्मीदवारों की संख्या में पिछले चुनाव की अपेक्षा वृद्धि होने के आसार हैं।

विधानसभा से बिल पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी निकाय चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दे रखे हैं।

आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विवि बनेगा–

आमेर में 101 करोड़ की लागत से 2 लाख वर्ग मीटर भूमि में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। सात संभागों में एक-एक खेल कॉलेजों को भी संबद्धता दी जा सकेगी। खेल मंत्री के अनुसार इससे शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। इस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में अध्ययन कर सकेंगे। बायो मैकेनिक्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेटा एनालिसिस और न्यूट्रिशन साइंस में कॅरियर बनाने में भी यह विश्वविद्यालय मददगार बनेगा।

Newspaper of 15 March, 2026

होंडा (HONDA) कंपनी (टपूकड़ा संयंत्र) राजस्थान में EV (ईवी) उत्पादन करेगी; सीएम ने पहले मॉडल का अनावरण किया–

होंडा कंपनी की ओर से पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के टपूकड़ा (अलवर) संयंत्र में बनेगा, जिसका उत्पादन इसी वर्ष शुरु होगा। 14 मार्च, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होंडा के पहले ईवी मॉडल (होंडा 0 अल्फा) का अनावरण किया। सितम्बर 2024 में जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने होंडा के शीर्ष प्रबंधन को राजस्थान में ईवी मॉडल निर्माण एवं निवेश के लिए आमंत्रित किया था।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी खरीद पर अनुदान, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जा रही है। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट एवं सीईओ ताकाशी नाकाजिमा ने बताया कि यहाँ उत्पादित मेड इन इंडिया ईवी मॉडल घरेलू बाजार के साथ ही कई देशों में निर्यात किए जाएँगे।

देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान एसएमएस में तैयार हुआ–

- सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार है।
- निजी अस्पतालों में लाखों रुपए में होने वाला उपचार यहाँ आमजन को न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा।
- लंदन के बाद विश्व का यह दूसरा सबसे एडवांस एवं उत्कृष्ट संस्थान है, जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा।
- इस संस्थान में 4 प्रकार की अत्याधुनिक लेजर मशीनें जैसे डायोड लेजर और फ्रेक्शनल कार्बन डाई ऑक्साइड लेजर, एक्साइमर लेजर, एनडी-याग लेजर व अलेकजन ड्राइड लेजर स्थापित किए हैं, जो समस्त प्रकार की जन्मजात कॉस्मेटिक्स बीमारियों में काम में लिए जाते हैं।
- इस संस्थान में पीआरपी पद्धति द्वारा बाल उगाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर हाइफू मशीन द्वारा स्किन टाइट करके झुर्रियाँ हटाने का इलाज भी किया जाएगा।
- लेजर पद्धति द्वारा सफेद दागों व सोरायसिस का इलाज एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी व क्रायो द्वारा विभिन्न चर्म रोगों के इलाज की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

आईओटी आधारित स्मार्ट तकनीक के उपयोग पर राजस्थान स्टेट गैस को राष्ट्रीय 'डायमण्ड अवॉर्ड'–

राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (आरएसजीएल) को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 'डायमण्ड अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में इंडिया स्मार्ट ग्रीड फोरम द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। आरएसजीएल की ओर से यह पुरस्कार उपमहाप्रबंधक ने प्राप्त किया।

कंपनी को यह पुरस्कार सीएनजी मदर स्टेशन पर आईओटी आधारित स्मार्ट तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए दिया गया है। आएसजीएल द्वारा उन्नत आईओटी तकनीक के माध्यम से सीएनजी स्टेशनों का संचालन रियल टाइम निगरानी प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है। इससे डेटा एकीकरण, स्वचालित प्रबंधन, डिस्पेंसर और कंप्रेसर संचालन, परिचालन डेटा की मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग ऑफ शेड्यूलिंग जैसी गतिविधियां एकीकृत आईओटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित हो रही हैं। सीएनजी मदर स्टेशन के इस ऑटोमेशन से कार्य में पारदर्शिता और रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित हुई है।

Newspaper of 16 March, 2026

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ओडीओपी और 'जयपुर रत्नम्' प्रदर्शनी शुरू हुई–

15 मार्च, 2026 को राजस्थान दिवस के अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआइसी) में राज्य स्तरीय ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) और 'जयपुर रत्नम्' प्रदर्शनी शुरू की गई। जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, जिला कलक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी और उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रदर्शनी में प्रदेश के सभी जिलों के ओडीओपी उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें लोग मौके पर खरीद भी सकते हैं। इसमें कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी का आयोजन 15 मार्च-19 मार्च, 2026 तक किया गया।

नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ–

15 मार्च, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर हाउस में 'राजस्थान उत्सव 2026' का शुभारंभ किया। 25 मार्च तक आयोजित होने वाला यह उत्सव राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, लोकसंगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक व्यंजनों की झलक प्रस्तुत करेगा।

सीएम शर्मा ने मेले में राजीविका और ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रूडा) की तरफ से लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और राजीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद किया। बीकानेर हाउस परिसर में सीएम शर्मा ने राजस्थानी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें राजस्थान के लोकजीवन, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं को आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

Newspaper of 18 March, 2026

राजस्थान जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बना–

17 मार्च, 2026 को राजस्थान ने 'हर घर जल' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई गाइडलाइन्स के अनुसार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाले देश के पहले राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है।

यह एमओयू केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल की गरिमामय उपस्थित में जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया।

इस पहल के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और दैनिक जीवन अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनेगा।

यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ एवं नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सेवा गुणवत्ता में सुधार, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Newspaper of 20 March, 2026

राज्य में खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में विश्व रिकॉर्ड बना, दो दिन में 48 हजार फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण दिया–

राजस्थान में शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के

उद्देश्य से मिलावट के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। तथा आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है।

- खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने मात्र दो दिनों (17 एवं 18 मार्च) में 48 हजार से अधिक खाद्य कारोबारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- पहले ही दिन 30 हजार से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया, जो भी एक रिकॉर्ड है।
- खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम सहित जिलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों ने खाद्य सुरक्षा की दिशा में यह ऐतिहासिक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, मिड-डे मील कर्मी, राजकीय छात्रावासों के स्टाफ, जेल रसोई कर्मचारी, होटल एवं ढाबा संचालक तथा स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित विभिन्न खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- इस उपलब्धि को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जो कि प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। विभाग को इसका अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।

■ राजस्थान यूनिवर्सिटी, आरकेसीएल के बीच एमओयू हुआ; ग्यारह रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिली मान्यता–

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की इंटर्नशिप के लिए राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) के 4 क्रेडिट/120 घंटे के 11 रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है।

कुलगुरु सचिवालय में राजस्थान यूनिवर्सिटी और आरकेसीएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

आरकेसीएल के इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को ऑडियो विजुअल कंटेंट, हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग एवं प्रोजेक्ट्स की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ऐसे में आरकेसीएल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस्ड एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डीटीपी, वेब डवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, पायथन प्रोग्रामिंग एवं एआइ और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समेत कई आधुनिक और रोजागारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को यूनिवर्सिटी की ओर से मान्यता प्रदान की गई है।

■ हर पंचायत-वार्ड का मास्टर प्लान बनेगा; सीएम ने वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण किया–

19 मार्च, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास से राजस्थान दिवस के अवसर पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। गांव से लेकर शहर से वार्डों तक विकास की नई पहल को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए।

15 मई तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान के तहत शुक्रवार को ग्राम पंचायतों में पहली ग्राम सभा तथा सभी शहरी वार्डों में वार्ड सभा आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से अभियान की रूपरेखा के बारे में आमजन को अवगत कराया जाएगा। इसके पश्चात चरणबद्ध रूप से अन्य ग्राम एवं वार्ड सभाएँ आयोजित होंगी। पंचायत स्तरीय व वार्ड स्तर की टीम द्वारा आमजन से चर्चा कर डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

Newspaper of 21 March, 2026

■ अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस; अटल वन का उद्घाटन, वन सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत–

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 460 मोटरसाइकिलों और इमरजेंसी वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी

अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस के अवसर पर झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RRC) में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि और वन मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने घायल वन्यजीवों के रेस्क्यू के लिए आपातकालीन वाहनों को रवाना किया और वन सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के लिए 460 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर शाहपुरा में विकसित किए गए अटल वन का उद्घाटन भी किया गया।

Newspaper of 22 March, 2026

■ राज्य में जीआइएस आधारित ग्रीनलैंड यूज प्लान बनाने के लिए कमेटी गठित की; ₹30 करोड़ का प्रावधान किया–

प्रदेश में जमीन के बेहतर और पर्यावरण अनुकूल उपयोग के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट में जीआइएस आधारित ग्रीन लैंड यूज परस्पेक्टिव प्लान तैयार करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

इस योजना को लागू करने के लिए शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने दस सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसकी अध्यक्षता विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे।

सरकार का मानना है कि इस योजना से शहरों का विस्तार अनियोजित तरीके से होने के बजाय सुव्यवस्थित होगा। साथ ही पार्क, ग्रीन बेल्ट और खुले क्षेत्रों में वृद्धि होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। विकसित राजस्थान के विजन के तहत यह पहल शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- **राजस्थान में E-GRAS की जगह नए रेवेन्यू मैनेजमेंट से होगा राजस्व संग्रहण–**

राज्य सरकार ने राजस्व संग्रहण तंत्र में बड़ा बदलाव किया है। अब e-GRAS के स्थान पर IFMS 3.0 के अंतर्गत विकसित रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) से राजस्व संग्रहण किया जाएगा। ये सभी विभागों में 11 अप्रैल से प्रभावी होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय राजस्व प्राप्तियों, चालान जनरेशन, भुगतान और लेखा प्रेषण की प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जाएगी। परिपत्र के अनुसार आरएमएस के माध्यम से नागरिकों को एसएसओ लॉगिन, ऑनलाइन सेवा चयन और मैनुअल चालान जनरेट करने की सुविधा मिलेगी। विभागों के लिए एक्सेस वर्क स्पेस, मौजूदा सेवाओं और करों की उपलब्धता तथा क्विक चालान की व्यवस्था भी IFMS 3.0 के जरिए जारी रहेगी। सरकार का उद्देश्य राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी सुगम और जवाबदेह बनाना है।

- **21 मार्च, 2026 को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने परिवार सहित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। यहाँ उन्होंने गिरिराज जी के दर्शन कर दूध से अभिषेक किया। राष्ट्रपति ने 21 किमी. की गोवर्धन परिक्रमा की जिसमें कुछ दूरी पैदल व बाकी गोल्फ कार्ट में की।**

  उल्लेखनीय है कि द्रोपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की है।

- **राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026; देश की सामरिक आत्मनिर्भरता में राजस्थान निभाएगा अहम भूमिका, मिसाइल भी बनेगी–**

राजस्थान में एयरोस्पेस एवं डिफेंस नीति, सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी लागू हो गई है। इन नीतियों से प्रदेश को रक्षा, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केन्द्र बनाने के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन से लेकर निर्माण तक का संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा।

- **राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–**चिप डिजाइन से लेकर चिप बनाने तक का पूरा सिस्टम राजस्थान में ही विकसित होगा।

  छूट–7 वर्ष तक बिजली शुल्क में पूर्ण छूट, स्टाम्प शुल्क और भू-रूपांतरण शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर्यावरणीय परियोजनाओं पर लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, रोजगार प्रोत्साहन। राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत प्रमाणित इकाइयों को सहमति शुल्क में 50 प्रतिशत (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए)
- **जोधपुर, पाली, मारवाड़ को कॉरिडोर के तौर पर डवलप करेंगे–**यह पॉलिसी केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसमें रिसर्च, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग सभी चरण शामिल किए गए हैं। जोधपुर-पाली-मारवाड़ क्षेत्र, कांकणी औद्योगिक क्षेत्र समेत कई जगहों को सेमी कंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ उद्योगों को जमीन, बिजली, पानी और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएँ तेजी से मिलेंगी।
- **एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी–**विमान, यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन), मिसाइल, एवियोनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एमआरओ (मेंटीनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस) और प्रिसिजन इंजीनियरिंग (इसमें उच्च सटीकता और जटिलता वाले कल-पुर्जे व सिस्टम बनाए जाते हैं) निर्माण कार्य वाली इकाइयाँ स्थापित होंगी। प्रदेश में बंदूक ओर आर्मर्ड वाहन बनाने की यूनिट लगाई जाएंगी।

  3 श्रेणियों में प्रोजेक्ट–विनिर्माण क्षेत्र में 50 से 300 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 से 1000 करोड़ पर मेगा और 1000 करोड़ से अधिक पर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट माने जाएंगे। सेवा क्षेत्र में 25 से 100 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएँ लार्ज, 100 से 250 करोड़ मेगा और 250 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा श्रेणी में आएंगे। निवेशकों को विशेष इंसेंटिव भी दिए जाएंगे।

  ये मिलेगी राहत–बिजली ट्रांसमिशन और अन्य चार्जेज में छूट, सात साल तक बिजली शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा। 7 साल तक मंडी और बाजार शुल्क भी वापस मिलेगा। स्टाम्प या जमीन रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और 25% राशि वापस दी जाएगी।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- **इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी**–राजस्थान को बड़ा औद्योगिक हब बनाने के लिए यह नीति तैयार की गई है। इसमें निजी डवलपर्स को औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति होगी, लेकिन निगरानी रीको के तहत रहेगी।
  ये सुविधाएँ–100 एकड़ से 250 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों के लिए 20 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी। स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क पर 25 प्रतिशत भुगतान से छूट एवं 25 प्रतिशत पुनर्भरण।

Newspaper of 25 March, 2026

- **मार्च, 2026 में राज्य के जैसलमेर जिले के राष्ट्रीय मरू उद्यान (डीएनवी) के गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान और प्राकृतिक तरीके से दो और चूजों का जन्म हुआ है। ब्रीडिंग सेंटर्स में प्राकृतिक और वैज्ञानिक तकनीक से गोडावण के जन्म का यह मार्च, 2026 में चौथा मामला है। उल्लेखनीय है कि इसी के साथ जिले के रामदेवरा व सुदासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावण की कुल संख्या 74 तक पहुँच गई है।**

Newspaper of 30 March, 2026

- **हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज ने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू कर दी है। सरपंचों को अब ₹7347 मिलेंगे। प्रधानों को ₹12858 और जिला प्रमुख को ₹18368 मिलेंगे।**

Newspaper of 31 March, 2026

- **'उड़ान यात्री कैफे' जयपुर सहित देश के 11 एयरपोर्ट पर सुविधा शुरू हुई; एयरपोर्ट पर ₹10 में चाय, ₹20 में समोसा या बड़ा पाव मिलेगा–**

  30 मार्च, 2026 को केन्द्र सरकार ने जयपुर सहित देश के 11 प्रमुख एयरपोर्ट पर 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत की है। यहाँ यात्रियों को सस्ते दाम पर चाय, नाश्ता और पेय पदार्थ मिलेंगे। चाय ₹10 में, जबकि समोसा व बड़ा पाव ₹20 में मिलेंगे। पानी की बोतल ₹10 व कॉफी ₹20 में मिलेंगी।

□□□

संजीव प्रकाशन

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

51 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

कैलाश नागौरी की प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हिन्दी की उपयोगी पुस्तकें

संजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें

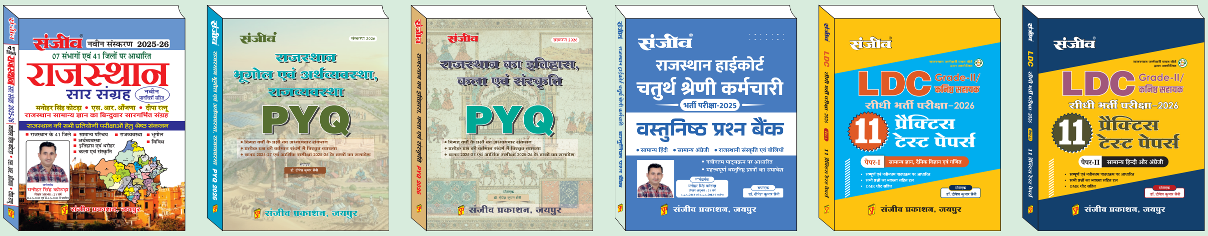

संजीव Telegram चैनल, App एवं Website से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्राप्त करें। साथ ही संजीव App एवं वेबसाइट से आप Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।

Join Our App

Join Our Telegram

प्रकाशक-संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com